been taken up to identify posts at various levels that could be surrendered/abolished The review is still in progress. It is not possible at this stage to indicate the percentage of reduction in expenditure on account of abolition/surrender of posts.

(d) Central Civil Services (Redeployment of Surplus Staff Rules, 1990, lay down detailed guidelines for redeployment of surplus personnel.

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को प्राथमिकता

844. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछड़े जिलों में केवल ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दे रही है जिनके लिए विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्यवार प्रतिवर्ष ऐसी कितनी परियोजनायें आरंभ की गई; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों में आरंभ किए जाने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सरकार द्वारा प्राप्त की गई विदेशी सहायता, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध संसाधनों के केन्द्रीय भंडार में पहुंच जाती है और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के बीच उसका आबंटन हमारी आयोजनागत प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि, योजना तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को उचित अंश दिया जाये।

(ख) सूचना नीचे दी गई है :—

इन वर्षों में परियोजनाओं की संख्या

राज्य का नाम	1988 −89	1989 −90	1990 −91
आंध्र प्रदेश	1	3	4
गुजरात	—	1	—
कर्नाटक	4	5	—
केरल	1	—	—
मध्य प्रदेश	3	—	—
महाराष्ट्र	1	1	1
उड़ीसा	2	1	—
पंजाब	—	2	—
राजस्थान	1	3	—
तमिलनाडु	3	5	3
उत्तर प्रदेश	2	1	4
पश्चिम बंगाल	2	—	3
बहुराज्य	2	—	8
जोड़	22	22	23

(ग) विदेशी संसाधन, योजना अवधि के दौरान कुल निवेश परिव्यय और उपलब्ध आंतरिक संसाधनों के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए जुटायें जाते हैं। सहायता की राशि हमारी वर्ष-दर-वर्ष सहायता संबंधी आवश्यकताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय सहायता की स्थिति पर निर्भर करती है। 1 अप्रैल, 1992 से शुरू होने वाली आठवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और इसलिए आठवीं योजना की अवधि के दौरान परिकल्पित राशियों तथा आवश्यक विदेशी सहायता के स्वरूप के बारे में इस समय कुछ बताना संभव नहीं है।

Release of foreign exchange for import of cotton

845. DR. YELAMANCHILI SIVAJI. Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government consideration to release foreign exchange to import cotton; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Yes, Sir.

(b) A proposal for import of cotton is being processed for decisions including on the quantity to be imported, modalities of import,, duty levels and earmarking the imported cotton for the benefit of handloom weavers. Final decisions in the matter are yet to be taken.

Credit squeeze in Nationalised Banks

846. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of FINANCE be pleased 10 state:

(a) whether it is a fact that credit squeeze is continuing among nationalised banks for the last ten months;

(b) if so. what are the reasons therefor; and

(c) by when it is likely to be lifted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) No, Sir. There is at present no credit squeeze imposed on the banks by the Reserve Bank of India (RBI). In order to moderate monetary and credit expansion, temporarily for the period between May S, 1991 and September 30, 1991 credit drawals of Rs. one crore and over from banks was restricted to the peak level of actual utilisation by them in the same period in the previous three years or the cash credit limits sanctioned to them as on May 8, 1991 whichever was lower. This measure is no longer in force. Due to resources constraint some banks may have to effect control on credit expansion, but for the system as a whole the credit policy frame-work ensures an adequate level of credt.

देश पर आन्तरिक तथा विदेशी ऋण

847. श्री अनन्तराम जायसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के दशक की शुरूआत में देश पर विदेशी तथा आंतरिक ऋण का बोझ अलग-अलग कितना था और 1986 के वित्तीय वर्ष तथा 15-2-92 को यह ऋण बढ़कर कितना हो गया था ;

(ख) क्या सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में देय विदेशी ऋण (मूल तथा ब्याज) की किश्तों के भुगतान के पश्चात् शेष रहने वाले विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति का आकलन किया है ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष तथा पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान विदेशी कर्ज पर ब्याज के भुगतान के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई और ऋण की कितनी मूल राशि वापिस की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राशेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1980-81 और 1986-87 के अंत में देश पर बकाया विदेशी ऋण क्रमशः 18400 करोड़ रुपए तथा 49069 करोड़ रुपए था । 15 फरवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार विदेशी ऋण की स्थिति उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस अवधि के लेखों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

वर्ष 1980-81 और 1986-87 के अंत में बकाया आन्तरिक ऋण और केन्द्र सरकार की अन्य देनदारियां क्रमशः 48151 करोड़ रुपए और 145947 करोड़ रुपए थीं और वर्ष 1991-92 के अंत में इनके 317379 करोड़ रुपए होने का अनुमान है ।

(ख) विदेशी मुद्रा भंडारों की स्थिति का न केवल पूर्ववर्ती ऋणों की वापसी अदायगियों और ब्याज भुगतानों की अनुमानित अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर लगातार आकलन किया जाता है अपितु व्यापार में खाते में अन्तर्प्रवाह/बहिर्प्रवाह (निर्यात और आयात भुगतान) की संभावनाओं, अदृश्य खाते में विभिन्न प्रवाह, अनुमानित सहायता संवितरण और अन्य पूंजीगत लेनदेनों को भी ध्यान में रखा जाता है ।